

**जय भीम**

**जय रिपब्लिकन**

**जय भारत**

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर व उनकी रिपब्लिकन पार्टी जनतन्त्र की कामयाबी के लिये :- मैंने बौद्ध धर्म को इस लिये पसन्द किया क्यो की इस मे तीन बातों का समावे" है जो किसी अन्य धर्म मे नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा करुणा एवं समता को सिखाता है। इनसे ही मनुष्य का जीवन अच्छा एवं सुखी होता है।

**डॉ. अम्बेडकर**



**बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब**

**डा० अम्बेडकर के अमूल्य रत्न**

“मैं आपसे आ"वासन चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये निष्ठापूर्वक संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे और अधिकार प्राप्त होने तक पीछे नहीं हटेगें।”

**जय भीम**

**जय रिपब्लिकन**

**जय भारत**

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर व उनकी रिपब्लिकन पार्टी जनतंत्र की कामयाबी के लिये :-

**1-** पार्टी के इस कारवां में हर वे व्यक्ति शामिल हो सकते है जो शोषण और बेइमानी से सम्पत्ति, शिक्षा, भूमि, उद्योग, पद नेतृत्व आदि पर की गई कब्जेदारी को उनकी सभी शक्तों में समाप्त होते देखना चाहते हैं।

**2-** अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिये संघर्ष करने में अपना गौरव समझते हैं।

**3-** जो यह मानते है की शोषण बहुत बड़ा पाप तथा शोषक बहुत बड़ा अपराधी है।

**4-** जिन कारणों से समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है उनका अन्त करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

**5-** जो मालिक और मजदूर तथा छोटी जाति बड़ी जाति के बंधन स्वीकार नहीं करते।

**6-** जो मानवधिकार के लिये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं का अन्त कर मानवता का मस्तक ऊंचा करना चाहता है।

**7-** जिन्होंने भय, अभाव, मंहगाई, भ्रटाचार आंतक, उत्पीड़न, आदि अमानवीय कुकृत्यों से ग्रस्त जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिये किसी भी मानवीय संघर्ष में कूद पड़ने का मन बना लिया है।

**8-** जन तांत्रिक सरकार के साथ ही जनतांत्रिक समाज का निर्माण चाहते हैं।

**9-** ऐसी सरकार चाहते हैं जहां हर एक को बराबरी के साथ बराबर बढ़ने का मौका मिले।

**10-** जो पूँजीवाद व साम्यवाद के बीच के रास्ते पर जहाँ स्वतंत्रता व समता का एकत्व ऊपर तथा पूँजीवाद व तानाशाही उसके नीचे हों चलने को तैयार हैं।

# दे"ा के स्वराज्य के साथ जनता के

## स्वराज्य के लिये संघर्ष की भूमिका

1. मानव को सभी प्रकार की उन्नति का अवसर। राजनितिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता, समान शिक्षा, जाति विहीन, वर्णविहीन समाज की रचना कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी पर अत्याचार न करे, गरीबी का नामोनि"ान न हो इसी का नाम स्वराज्य है।

2. स्वराज्य के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बाबासाहब ने सबसे पहले उस वर्ग को जो सभी प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित था। सब प्रकार से अवनति को प्राप्त हो चुका था संगठित किया। उसे अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु संगठित कर प्रेरित किया। उस संघर्ष में स्वयं आगे बढ़े ओर कामयाबी हासिल की पानी पीने का अधिकार, आम रास्तों पर बराबर चलने का अधिकार व सबके समान कपड़े पहनने का अधिकार, धार्मिक स्थलों पर प्रवे"ा का अधिकार, स्कूलों में शिक्षा हासिल करने अधिकार आदि के लिये स्वयं को समर्पित कर जन चेतना की लहर पैदा की।

3. दे"ा को स्वराज्य देने निमित्त, उसके संविधान का मसविदा तैयार करने के लिये, ब्रिटे"ा गवर्नमेंट ने 1930 ई0 में लंदन में भारत के सभी वर्गों के प्रतिनिधि आमंत्रित किये उनमें बाबासाहब डा0 अम्बेडकर भी थे। बाबासाहब की बहस का सारां"ा था, कि दे"ा को राजनैतिक प्रजातंत्र के साथ सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की गारंटी होनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर राजनैतिक प्रजातंत्र ज्यादा दिनों टिक पाना सम्भव नहीं है। इसके लिये जनता की जनता द्वारा के वास्ते सरकार बनाने के सिद्धान्त अमल में लाने चाहिए।

4. ऐसा करने के लिये हर बालिग को जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी हो वोट का अधिकार मिले। जात-पाँत, के रहते अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति के लोग जो की हीनावस्था में सब प्रकार से अधिकार विहीन जीवन बिता रहे हैं, उन्हें अपनी बात कहने और अपनी समस्याओं को अपने आप रखने के लिये कुछ सुरक्षित

सीटों पर प्रारम्भ में केवल 10 साल के लिये अपना प्रतिनिधि अपने आप चुनने का अधिकार होना चाहिये।

5. अल्पसंख्यकों को अधिकारों के नियम के साथ उनकी सुरक्षा की भी गारण्टी भी संविधान द्वारा दी जाय।

6. गांधी जी ने दावा किया कि कांग्रेस ही सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले केवल कांग्रेस की राय से ले। कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में वे (गांधी जी) यहां उपस्थित हैं उन्होंने कहा की डा० अम्बेडकर को अछूतों के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। वे अछूत के प्रतिनिधि नहीं हैं। अछूतों के प्रतिनिधि भी वही (गांधी जी) है।

7. गांधी जी ने मुसलमानों और सिखों के पृथक निर्वाचन की मांगें तो स्वीकार कर ली पर बाबासाहब द्वारा प्रस्तुत अछूतों की मांगें मानने से इन्कार कर गये। बाबासाहब चाहते थे की संविधान में अछूतों का कानूनी अधिकार मान लिया जाय। अल्पसंख्यक समिति ने इसे मान लिया पर गांधी जी ने नहीं माना। वे इस निर्णय को ब्रिटिश गवर्नमेंट पर छोड़कर चले आये। सन 1932 ई० में भारत को मिलने वाला स्वराज्य टल गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अछूतों को बीस साल के लिये पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी।

8. घोषणा होते ही गाँधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने पूना पैक्ट की यरवदा जेल में अछूतों के आरक्षण के विरुद्ध आमरण अन्याय प्रारम्भ कर दिया। उनकी जान खतरे में घोषित हो गई। लन्दन में उन्होंने बाबा साहब को अछूतों का प्रतिनिधि नहीं माना था। यहाँ कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता तथा कस्तूरबा गाँधी आदि ने बाबासाहब से अपील की कि वे गाँधी जी की जान बचा लें। बाबासाहब का कहना था की गाँधी जी की जान उन्हें भी प्यारी है पर उससे अधिक अछूतों के अधिकार प्यारे हैं जिन्हें वे अपने जीते जी छोड़ नहीं सकते।

9. बाबासाहब को मार डालने की धमकियां दी गईं, वे डिगे नहीं बाबासाहब पर इतना दबाव डाला गया कि जितना संसार के किसी नेता पर न पड़ा होगा। गांधी जी ने स्वयं कहा की मेरी जिन्दगी आपके हाथ में है मेरी इज्जत पर मुझे छोड़

दीजिए। मैं बहुत धिक्कार पात्र मनुष्य हो सकता हूँ -----। पूना पैक्ट की कुछ शर्तें हुरीं जिसमे यह भी था कि सुरक्षित सीटों पर कागेंस दखल नहीं देगी। बाबा साहेब ने साफ साफ कहा “मुझे तो अछूतों के लिये राजनैतिक सत्ता चाहिये। हमारे जीते रहने के लिये यह अनिवार्य है” ।

**10.** पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर के बाबासाहेब ने गांधी जी की जान बचा ली। बाबा साहेब ने बताया की यदि मैं गाँधी जी के प्राण नहीं बचाता तो दे”ा की शान्ति भंग करने वाला मानवता का शुत्र आदि कहा जाता। और मेरे साथ अछूतों को भी इस लॉछन का भागी होना पड़ता। अतः मैंने बड़े व्यथित हृदय से गाँधी जी की शर्तों पर समझौता करना स्वीकार कर लिया।

**11.** वह समझौता दस वर्ष के लिये था। इस बीच बाबासाहेब को देखना भी था कि कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस का नेतृत्व गाँधी जी के हाथ में था। गाँधी जी छूआ-छूत मिटाने तक तो राजी हुए पर वर्ण जाति को बनाये रखने के पक्ष में रहे। बाबासाहेब का कहना था कि मैं ऐसे आदमी को जो जात-पाँत या धार्मिक भेद-भाव मे वि”वास रखता हो दे”ा का नेता मामने के लिये तैयार नहीं। ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों के दु”मन है क्योंकि वे दोनों समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के विरुद्ध हैं। जात-पाँत व वर्ण व्यवस्था ने काम का विभाजन नहीं अपितु आदमी – आदमी का विभाजन किया है। कुछ में उच्चपन का अभिमान और कुछ में हीनता की गिरी हुई भावना । जिस व्यक्ति का मन ही मार दिया गया हो उसमें उच्चआकांक्षा कहाँ से आयेगी बलवान मन में ही धैर्य होता है। धैर्य से ही मुसीबतों से पार हुआ जाता है।

**12.** बाबासाहेब ने सोचा की जिन परिस्थितियों में दबकर आदमी दासवृत्त जीवन बिता रहा है। यदि वे परिस्थितियाँ बदल दी जाय और अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया जाय। तो व्यक्ति की हीन भावना समाप्त होकर वह मजबूत हृदय से आगे बढ़ेगा। उसे आध्यात्मिक कल्याण के बजाय भौतिक क्लायण के लिये अग्रसर किया जाय। यह काम राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से ही हो सकता है, जिसके लिये संघर्ष शील राजनीतिक संगठन की आव”वयकता है। इस संगठन का नाम बाद में बाबासाहेब डा0 अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी रखा।

**13.** लोगों को बताया जाय की हिन्दू समाज का एक हिस्सा बने रहने से सम्मान और समानता का दर्जा अच्छा है। उनमें अपनी दासता अपने आप समाप्त करने की प्रेरणा भरी जाय। इन्हें शिक्षित होने, संगठित होने, और संघर्ष करने के लिये प्रशिक्षित किया जाय। इनमें ऐसे विद्वान निकले जो शासन के किन्हीं पदों पर बैठकर अपने गरीब और निरीह लोगों की देखभाल कर सकें। ऐसे नेता निकले जो दूसरों से अच्छे ईमानदार, लगनशील और प्रतिभावान हों। किसी के पिछलग्गू या जनता के दलाल न हों समय और परिस्थितियों के अनुसार जनता की मागों की वकालत करें। राजनीतिक दल में सभी लोग अनुशासित होकर रहें। पार्टी के कार्यक्रम आइने की भाँति साफ हों। संस्था के पीछे नौजवानों की शक्ति हो जो हर मौके पर पीड़ित जनता की सहायता करने में समर्थ हो। (नौजवानों की इस संस्था का नाम समता सैनिक दल रखा गया)।

## यह कैसा स्वराज्य

**1.** देखते ही देखते कागज पर खेती करने वाला बड़ा किसान बन गया। अपनी प्रभुता व रूतबा बरकरार रखने वाला देहा भक्त हो गया। समाज सेवा का मन नहीं पर नेतागिरी के पैरे में समाज सेवक हो गया। जिनके पास सब कुछ था वे एसो आराम के मंसूबो में आगे बढ़े और जिनके पास कुछ भी नहीं था वे रोटियों की तलाश में भटकने लगे।

**2.** स्वराज्य के नाम पर राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिये कांग्रेस में ऐसे लोगों का समावेश हो गया जिनका कि अतीत में दलित व पिछड़ों के सामाजिक व धार्मिक आर्थिक जीवन पर एकाधिकारी जारी रहा। बड़े बड़े धनी लोगों ने कांग्रेस को चन्दे के रूप में धन की थैलियां खोल दीं। ताकि कांग्रेस उनसे प्रभाव में रहें। उस धन की बदौलत चुनाव में बेईमानी हो और जनता अपना असली प्रतिनिधि न भेज सके।

**3.** बाबासाहेब का सम्पर्क मिल मजदूरों से बहुत बचपन से था। वे उनकी दुख-पीड़ा को खूब समझते थे। वे जानते थे की मालिक और मजदूर के सम्बन्ध गुलामी के द्योतक है। मजदूर भी अपने हक की मागों के लिये मिल मालिक के खिलाफ उठ खड़ा हो। इसलिये उन्होंने मजदूरों में काम शुरू किया। आगे चलकर जब यह

वायसराय की इक्जीक्यूटिव के लेबर मेम्बर होये तो यूनियनों को मान्यता, छुट्टी तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के कानून बनाये।

4. बाबा साहब ने देखा कि मिल मालिकों, पूँजीपतियों, जमीदारों ओर प्रतिक्रियावादियों के नियन्त्रण में कांग्रेसी स्वराज्य रहेने से यह स्वराज्य अछूत, मध्यम वर्ग गरीब व पिछड़े वर्ग के घरों के कतई पहुँचने वाला नहीं है।

5. यही धनी वर्ग के लोग अपनी प्रभुता और स्वार्थ के लिये सत्ता पक्ष व सत्ता की ओर बढ़ने वाले दल को धन देंगे। जिससे चुनावों में बेईमानी की सम्भावनायें बढ़ेगी और इस बेईमानी के कारण जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा।

6. सन् 1937 में बाबासाहेब ने इण्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी की स्थापना की। और बम्बई प्रदेश से चुनाव में 17 प्रत्यागियों खड़े किये। 15 प्रत्यागियों विजयी हुए। यह बाबासाहेब के प्रथम राजनीतिक दल की महान सफलता थी।

7. विरोधी पक्ष मजबूत हो इसलिये चुनाव में उनकी भी सहायता की। ब्राह्मण प्रत्यागियों के लिये भी खुलकर काम किया।

8. ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के सामने फिर वही पुरानी दलीलें होने लगी कि डा. अम्बेडकर तो अब खुले आम स्वतंत्र मजदूर दल के नेता हैं। वे अछूतों के नेता नहीं हैं। अतएव उन्हें अछूतों के अधिकारों के सम्बंध में पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं है।

9. ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के अछूतों के सम्बंध में उनकी स्थिति और अधिकारों की जांच के लिये कमीशन बनाया। बाबासाहब ने अपना कतर्ब्य समझा कि वे अछूतों को अपनी मार्गें प्रस्तुत करने के लिये उन्हें तैयार करें।

10. श्री क्रिप्स ने बाबासाहब से प्रश्न कर दिया कि वे अछूतों के नेता हैं अथवा मजदूर दल के? इस सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अछूतों का पृथक राजनैतिक दल बनाए बगैर उनके अधिकारों के सम्बंध में मजदूर दल के माध्यम से संघर्ष करने में कांग्रेस बहुत बड़ी बाधक सिद्ध होगी।

**11.** एक ओर सारा दे"ा मिलकर दे"ा की आजादी की बात करें, तो दुसरी ओर सदियों से गुलाम इन्सानों की आजादी के उठते होये सवाल को दबाने का 'डयंत्र हो ऐसी संकट स्थिति में रास्ता निकालना आसान न था।

**12.** बाबा साहब ने अनुभव किया कि अछूतपन से पैदा हुआ सामाजिक रास्ता न केवल उन्हे सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का हिस्सा लेने के अयोग्य बनाता है, बल्कि उनके लिये किसी भी ऐसे अवसर की प्राप्ति असम्भव बना देता है, उन्हे किन्ही भी ऐसे नागरिक अधिकारों का अधिकारी नहीं रहने देता, जिस पर मानव का सारा अस्तित्व ही निर्भर करता है।

**13.** यहाँ पर हर नीची सीढ़ी का वर्ग उपर वाले को सम्मान की दृष्टि से देखता है और हर उपर का वर्ग नीचे की सीढ़ी वाले को घृणा की दुष्टि से देखता है। यह सिद्धान्त बराबर अन्याय पूर्ण है।

**14.** यह असमानता केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि अनेक रूपों में मानव की प्रगति में पग-पग पर रोड़ा बनी हुयी है तथा शोषक जातियों का स्वरूप ले चुकी है। शोषकों व शोषितों का यह स्वरूप लोकतंत्र के रास्ते में सबसे बड़ा व्यवधान है।

**15.** यह स्थिति दो समाजों के कलह का प्र"न है। एक समर्थक समाज द्वारा दूसरे असमर्थ समाज पर हो रहे अतिक्रमण का प्र"न है। यह एक मनुष्य पर हो रहे अन्याय का प्र"न नहीं. बल्कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर जबरदस्ती किये जा रहे अतिक्रमण का प्र"न है एक वर्ग द्वारा जो सदियों से समर्थ है शक्ति"ाली है निर्धन निर्बल, दलित वर्ग पर किये जा रहे जुल्म व शोषण तथा उत्पीड़न का प्र"न है। जिसे हल करने की चिन्ता कांग्रेस या किसी अन्य दल को नहीं है।

**16.** पूना पैक्ट के बाद कांग्रेस ने सबसे बड़ी वायदा खिलाफी यह की कि उसने सुरक्षित सीटों को अपने हाथ में ले लिया। आरक्षित क्षेत्र ऐसे बनवाए जहां हिन्दुओं का बहुमत हो इससे शोषित समाज के साथ खुला धोखा हुआ क्यों कि प्रतिनिधित्व खुले आम शोषक समाज का हो रहा। वायदा किया था कि पूना पैक्ट



के बाद किसी को जन्म से अछूत नहीं माना जायेगा। कथनी और करनी का अन्तर साफ दिखाई पड़ने लगा।

## शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"न

1. संघर्ष तो शेड्यूल्ड कास्ट के खोये हुये अधिकारों के प्राप्त करने के लिये करना ही था। जुलाई सन् 1942 में नागपुर में आल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट कानफ्रेन्स बुलाई गयी। पूना पैक्ट के बाद स्थिति का जायजा लेते हुए पाया गया कि खोये हुये अधिकारों को प्राप्त करने के लिये राजनीतिक संगठन की महती आवश्यकता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के बगैर दलितों का समाज में समानता का दर्जा नहीं प्राप्त हो सकता। सभा ने सर्व सम्मति से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"न नामक संगठन बनाने का नि"चय किया। इसकी अध्यक्षता श्री एन0 विवराज ने की।

2. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"न ने चुनाव लड़ा। 90 प्रति"त शेड्यूल्ड कास्ट के प्राप्त मतों के आँकड़े निकाल कर बाबासाहेब ने दिखा दिया कि यह हमारी शक्ति है।

3. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"न ने बाबासाहेब के नेतृत्व द्वारा सरकार के सामने अछूतों की बहुत सी मागें पे"ी की।

4. अछूत विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा की सुविधायें प्राप्त हुई केन्द्रीय तथा रेलवे की नौकरियों में अछूतों के लिये 12.5 प्रति"त स्थान सुरक्षित हुए।

5. देहली में अपने बंगले पर बाबासाहेब हर गरीब से मिलते थे उनका निवास "इन्साफ की कोठी" नाम से कहा जाता था।

6. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"न की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि पूना पैक्ट पर दबाव डालकर बाबासाहेब से हस्ताक्षर करवाये गये। अछूतों के साथ अन्याय हुआ।

7. ब्रिटेन से एक पार्लियामेण्टरी डेलीगे"न भारत की राजनीतिक समस्याओं के जांच के लिये आया। यह डेलीगे"न शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"न के अध्यक्ष राव बहादुर एन.

पिंवरज से और बाबासाहेब डा० अम्बेडकर से मिला। कैबिनेट मिनिशन ने भारतीय नेताओं से परामर्श किया।

8. कांग्रेस तथा अछूतों के सारे मतभेद एक मौलिक प्रश्न पर दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण गहरे होते गये। वह मौलिक प्रश्न यह था कि अछूत हिन्दुओं से अलग एक पृथक सामाजिक समुदाय है या नहीं? इस प्रश्न पर अछूतों का दृष्टिकोण था कि वे एक स्वतंत्र समुदाय हैं। कांग्रेस का मत था कि वे हिन्दू समाज का एक अंग हैं और इस कारण उन्हें पृथक से कोई अधिकार दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं।

9. भारत के सारे हिन्दू अखबार कांग्रेस का साथ दे रहे थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि अंग्रेज को यही समझा रहे थे कि सवर्ण और अवर्ण हिन्दू में कोई अन्तर नहीं है।

10. 'इड़यंत्र' हो ही रहा था कि वायसराय की काउन्सिल में सीटों में अछूतों को कोई भी सीट न मिले। बाबासाहेब की मांग थी कि इन्हें 3 सीटें मिलनी चाहिए। अन्तोगत्वा बाबा साहब के प्रयास से अछूतों को दो स्थान प्राप्त हो गये।

11. पुनः 'इड़यंत्र' हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री क्लिमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि वायसराय की काउन्सिल में केवल एक ही अछूत सदस्य होगा वह भी कांग्रेस का प्रतिनिधि।

12. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने मांग की कि इस अंतः कालीन सरकार में 6 करोड़ अछूतों, 40 लाख सिक्खों और 30 लाख ईसाइयों को समान मान कर सबों को एक-एक सीट दी जाय यह अछूतों के साथ घोर अन्याय है। अछूतों का प्रतिनिधित्व आल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नहीं करता है। हिन्दूओं के वोटों के बहुमत के बल पर जीत कर जाने वाला अछूत, अछूतों का प्रतिनिधि किसी भी दसा में नहीं हो सकता।

13. 4 जून सन् 1946 आल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने इस अन्याय के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही का निर्णय लिया। सम्पूर्ण भारत में फेडरेशन ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ दिया। ऐसा आन्दोलन कांग्रेस के इतिहास में भी न हुआ होगा।

14. नौकरियों में 19 प्रतिशत आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेटिव के सत्याग्रह आन्दोलन में रखी गई मागों में से एक है।

15. तय हुआ कि भारत का भावी विधान बनाने का कार्य विधान निर्मात्री परिषद करेगी।

16. कांग्रेस की ओर से पूरी चौकसी थी कि बाबा साहेब डा० अम्बेडकर इस विधान परिषद में न पहुँच पायें। बंगाल शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेटिव के अध्यक्ष माननीय जोगेन्द्र नाथ खण्डल उन दिनों बंगाल सरकार के न्यायमंत्री थे। उन्होंने बाबा साहेब का बंगाल से नामांकन करा दिया।

17. बंगाल ऐसम्बली में कुछ योरोपियन सदस्यों के वोट थे जिन्होंने बाबा साहेब को वोट देने का वायदा कर लिया था।

18. कांग्रेस ने अन्दोलन शुरू कर दिया कि बंगाल ऐसम्बली के योरोपियन विधान परिषद के लिये वोट न दें क्योंकि भारतीय विधान से योरोपियनों से कोई मतलब नहीं है। भारतीय सरकार ने कांग्रेस की यह मांग सवीकार कर ली।

19. भारत के एक राष्ट्रीय दल का यह आदेस कि किसी भी दसा में डा० अम्बेडकर को विधान परिषद का सदस्य नहीं चुना जाना चाहिये। अछूतों के लिये यह बहुत बड़ी चुनौती थी।

20. माननीय मण्डल जी ने इस तगड़े विरोध और पग-पग पर पड़ने वाली कठिनाईयों के बावजूद भी सब्र और चतुराई से बाबा साहेब को विजयी बना दिया। किन्तु भारत विभाजन के बाद बंगाल का भाग पाकिस्तान में जाने के कारण बाबा साहेब का वहीं से प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया और वे पुनः बम्बई से चुनकर केन्द्र में आये।

21. अछूतों का भविष्य अन्धकार में देख आल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेटिव के अध्यक्ष राय बहादुर एन० कृष्णराज तथा बाबासाहेब अम्बेडकर को ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से मिलने लन्दन जाना पड़ा। राजनीतिज्ञों को समझाया जा चुका था कि अछूतों की मागें पाकिस्तान की तरह खतरनाक हैं। लेकिन बाबासाहेब की बातें सुनने के बाद

उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की मांग केवल जायज ही नहीं बल्कि जरूरी भी है।

**22.** बाबासाहेब ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री किल्मेंट एटली को दिया, जिसे पढ़कर उन्हें लाचार होना पड़ा कि अछूतों के साथ अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री के समझ में आया कि अछूतों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं “आल इण्डिया शेड्यूलड कास्ट फेडरे”न” कर रहा है। उन्होंने आ”वासन दिया कि यदि अछूतों के साथ अन्याय हुआ तो उसका भरपूर इन्तजाम होगा। तथा “अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है”।

**23.** बाबासाहेब के लन्दन पहुँच जाने से उन्हें उनके मि”न में काफी सफलता मिली। अछूतों की रक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा की आ”ग बंधी। मंजिल की सफलता मिल गई। हिन्दू विधानों की गुलामी में जकड़े अछूतों के कई युगों के बाद स्वतंत्रता की सांस लेने का मौका मिला। शेड्यूलड कास्ट फेडरे”न ने भारत के बनने वाले संविधान में अपने सुझाव रखने के लिये अपना मसविदा छपवा कर वितरित करा दिया।

**24.** इसे ही कहते हैं समय का चक्र। भारतीय संविधान बनाने का भार बाबा साहेब डा० अम्बेडकर पर ही पड़ा। प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें अपनी कैबिनेट में विधिमंत्री का पद दिया। बाबा साहेब संविधान की मसविदा समिति के चेयरमैन हुए।

**25.** 9 सितम्बर सन् 1946 ई० को डा. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हुए। पं० नेहरू ने प्रस्ताव रखा स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता प्राप्त प्रजातंत्र। बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव तब तक स्थगित रखा जाये जब तक कि इस सभा में मुस्लिम लोग व भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि न आ जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव में उन दिनों हीनों के लिये भी संकेत किया जाय जो भारत के मूलनिवासी हैं और सदियों से यातनाएं सह रहे हैं। पं० नेहरू जी को यह प्रस्ताव अगले अधिवे”न 20.1.1947 में पास हो गया।

**26.** बंगाल का वह हिस्सा जहाँ से बाबासाहेब चुन कर आये थे विभाजन में पाकिस्तान के पास चला गया। तब वे पुन. बम्बई लेजिस्लेटिव कौन्सिल से चुनकर

विधान निर्मात्री परिषद में पहुँचें। बाबा साहेब ने भारत के विभाजन को रोकने का भरसक प्रयत्न किया। उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भांति ही संयुक्त भारत (यूनाइटेड इण्डिया) का रूप स्वीकार कर लिया जाये। जब उनकी यह बात नहीं मानी गयी तो उन्हें कहना पड़ा कि यह विभाजन मुसलमानों को यह सोचने पर विवर्ण करेगा कि यूनाइटेड इण्डिया ही अच्छा हल था।

**27.** शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने जिसके आन्दोलन के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों को कुछ मिल पाया है। अपनी मागों को लेकर देखापि जर्बदस्त आन्दोलन किया। जिसमें लाखों सत्याग्रहियों को जेल की यातनाएं भुगतनी पड़ी। उन्हीं मांगों की बदौलत भारतीय संविधान में दलित व कमजोर वर्गों की सुविधाओं व संरक्षण को स्थान मिला है।

**28.** यद्यपि पिछड़े वर्गों ने अपने अधिकारों के लिये कोई आन्दोलन नहीं किया फिर भी बाबासाहेब ने न्यायिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से उन्हें भी सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन के लिये सुविधायें प्राप्त करने का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ दिया।

**29.** भारतीय संविधान के पास होने के बाद 25 अप्रैल सन् 1948 को बाबासाहेब लखनऊ में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की कान्फ्रेंस में आये। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के लिये वे जीवन भर लड़े उसे पूरा करने का अवसर मिलने से वे विधिमन्त्री बने और संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि न तो वे कांग्रेस सदस्य बने न कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और न कभी कांग्रेसी बनने का इरादा ही किया। कांग्रेसी सरकार ने उन्हें कैबिनेट में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। बिना किसी शर्त में बंधें निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुझे जिस समय प्रतीत होगा कि वहां ठहरने से लाभ नहीं, मैं बाहर निकल आऊंगा।

**30.** “पार्लियामेन्टरी प्रजातंत्र में एक क्रियाशील विरोधी दल अनिवार्य है। कांग्रेस किसी भी विरोधी को नहीं चाहती है। कांग्रेस विभिन्न मतों के लोगों को एक ही खेमे में इकट्ठा करना चाहती है”

**31.** कांग्रेस एक जलता हुआ मकान है। कांग्रेस के लोग ही उससे निकल रहे हैं। कांग्रेस में ही बहुत से लोग ऐसे हैं प्रबल विरोधी पक्ष की आव"यकता का अनुभव कर रहे हैं।

**32.** कांग्रेस में शामिल होने से कोई लाभ नहीं। दो पार्टियां बनी रहने में ही सुरक्षा है "मैं पत्थर हूँ कितनी भी गहराई में डाल दिया जाऊं फिर भी पत्थर ही निकलूंगा। तुम मिट्टी के ढेले के समान हो वहां पहुंच कर धूल जाओगे।"

**33.** "बालिग मताधिकार ने जनता के हाथों में सत्ता सौंप दी है। यू.पी. के डेढ़ करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट और दो करोड़ पिछड़े वर्ग के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें तो वे विधान सभाओं में आधी से अधिक सीटों पर अपने लोगों को पहुंचा सकते हैं। और इस प्रकार राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार कर सकते हैं।"

**34.** यह सचमुच बड़े खेद की बात है कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी- अपनी शक्ति का मान और अभिमान नहीं है इसी का यह परिणाम है कि कथित उच्च वर्गीय लोग शासन पर अपना अधिकार जमायें बैठें हैं।

**35.** परिगणित जातियां और पिछड़ा वर्ग परस्पर मिलकर दे"ा का बहुमत बनाते हैं। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि वे लोग दे"ा पर अपनी हुकूमत क्यों नहीं करते। आप राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिये परस्पर संगठित हों।

**36.** कितने दुख का विषय है कि पिछड़े एवं अछूत दोनों वर्ग जिनकी आव"यकतायें समान हैं परस्पर एक साथ नहीं हैं। इसका यही कारण हो सकता है कि पिछड़े वर्ग के लोग समझते हैं कि इनके साथ होने पर वे परिगणित हो जायेंगे इसलिये उन्हें डर है कि कहीं वे भी नीचे उतरकर अछूत जातियों के स्तर पर न आ जायें।

**37.** मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि ये पिछड़े वर्ग के लोग अपना एक अलग मोर्चा खड़ा करें अलग- अलग रहने से पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़ी हानि हुई है।

**38.** "मैं पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के बीच रोटी बेटी का चलन चलाने का उत्सुक नहीं हूँ। पिछड़े वर्ग के लोग अपनी सामाजिक पृथकता बनायें रख सकते

हैं। लेकिन इसका कोई कारण नहीं है कि वे अपने आपकी अपनी गिरी हुई हालत से उपर उठाने के लिये परस्पर मिलकर एक राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बना सकते।”

**39.** दे”ा की राजनीति में हिस्सा लेकर परिगणित जातियों ने जिस तरह अपनी हालत को कुछ अच्छा बना लिया है इसका कोई कारण नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी ऐसा क्यों नहीं करते।

**40.** बालिग मताधिकार की शक्ति आपकी की मुठठी में है। लोग उत्साह और साहस से काम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन पर यह मिथ्या वि”वास सवार है कि कांग्रेस सरकार हमे”ा बनी रहनी है। यह बिल्कुल गलत ख्याल है। जनता की लोकतांत्रिक शासन प्राणली में कोई भी सरकार हमे”ा नहीं बनी रहेती। आज एक पार्टी के हाथ में शासन है तो कल दूसरे के हाथ में होगा। यही बात हर सरकार के लिये सही है। पं० नेहरू और सरदार पटेल जैसे ऊंचे दर्जे के नेताओं के लिये यही सही है। यदि आप संघटित हो जाये तो आप अपनी सरकार बना सकते है।

**41.** मेरा पराम”ा यह है कि आपको एक तीसरी पार्टी के रूप में पृथक संगठित होना चाहिए। सिर्फ पिछलग्गुओं की तरह राजनीतिक दल में शामिल होने से कोई लाभ नहीं। यदि वह हमें कुछ भी दे सकती है तो दफतर दे सकती है। वह हमें शक्ति नहीं दे सकती।

**42.** बाबा साहेब ने लखनऊ में कान्फ्रेंस में जिस तीसरे दल को बनाने की घोषणा की थी उसे उन्होंने 13 अक्टूबर 1956 को स्वयं ही “रिपब्लिकन पार्टी” बनाने का प्रेस वक्तव्य दिया तथा 30 नवम्बर सन् 1956 को दिल्ली में आल इण्डिया शेडयूल्ड कास्ट फेडरे”ान को भंगकर फेडरे”ान के स्थान पर “भारतीय रिपब्लिकन पार्टी” की स्थापना कर दी। बाबा साहेब का अंतिम मार्मिक संदे”ा हमारे सामने है।

**43.** मेरे शोषित व गरीब भाईयों। मैंने तुम्हारे लिये जो कुछ भी किया है, वह बेहद मुसीबतों, अत्यन्त दुःखों और बे”ुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसिबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवाँ सदा आगे ही बढ़ता रहे बेसक कितनी ही रूकावटें क्यों न आएँ। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़

दें। पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। अपने लोगों से यही मेरा संदेश है।”

## रिपब्लिकन पार्टी की दिशा

1. बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समता व बन्धुता की रक्षा के लिये बनी है। न्याय का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का अर्थ है विचारों की अभिव्यक्ति विवास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता का अर्थ है पदवी, दर्जा और सब सुयोगों की प्राप्ति में समता। बन्धुता का अर्थ है व्यक्तिमय गौरव और एक राष्ट्रीयता में बन्धुता। इसे पाना ही हमारा लक्ष्य है।
2. हमने लोकतांत्रिक सरकार स्वीकार की है लोकतांत्रिक जीवन के साथ। हमने भारत के संविधान में अपने को जाति नहीं, वर्ग नहीं, भाषा नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सीमा में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक यूनिट बनाकर शब्द 'लोग' का प्रयोग किया है इस 'लोग' शब्द में ही धर्म निरपेक्षता का सार छिपा है।
3. राष्ट्रीय मुद्रा में सम्राट अशोक के स्तम्भ के शीर्ष भाग जिसमें चारों दिशाओं की ओर मुख करके बैठे हुए चार सिंह धर्म निरपेक्ष राज्य की गर्जना के प्रतीक हैं। इसक नीचे चौकी पर हाथी, बैल, अश्व और सिंह जोकि प्रत्येक के साथ दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बन्धुता के एकता के प्रतीक हैं। महान सम्राट अशोक का धर्म निरपेक्ष हमारा आदर्श है। (पेगावर के पास शाहवाज गढ़ के पत्थरों पर सम्राट अशोक के धर्म निरपेक्ष सम्बंधी वाली भाषायें लिखे लेख) का अर्थ है:- आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि कई रूपों में प्रकट होती है। पर उसकी जड़ है वाणी का संयम ताकि हम अपने धर्म की बढ़ाई करने से बच सकें वा दूसरे धर्म की निन्दा करने से बच सकें। सुयोग्य अवसर आने पर दूसरे धर्म के मानने वालों का समुचित सम्मान करना चाहिए। इस तरह हम स्वयं अपने धर्म वालों का सम्मान बढ़ाते हैं और दूसरे धर्म वालों की भी सहायता करते हैं। इससे विपरीत चलने पर



हम अपने धर्म को भी नुकसान पहुँचाते हैं और दूसरों के धर्म का भी उपकार करते हैं जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे धर्म की निन्दा करता है व उसे अपने धर्म से नीचा दिखाता है, और अपने धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा मानता है वह वास्तव में अपने धर्म को सबसे अधिक हानि पहुँचाता है।

4. रिपब्लिकन पार्टी के सामने धार्मिक एकताओं के बजाय भारतीय एकता का सवाल है। हम गरीबी के सबसे बड़े दो कारणों भय व अभाव को समाप्त कर व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाते हुए सुखी जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें भ्रष्टाचार की संस्कृति मिटानी होगी।

5. हमने अपने कार्य की दिशा प्रतिज्ञाबद्ध सिद्धान्तों को सम्मुख रखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आधार मिला मान कर निर्णय की है- पार्टी भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित समजवाद, धर्म निरपेक्ष तथा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ निष्ठावान रहेगी। इस सम्बंध में हमारी पार्टी बाबा साहेब का सारगर्भित सिद्धान्त अपना रखा है-

“राष्ट्रीयता एक सामाजिक चेतना है, एकता के संयुक्त भावों का आभास ही राष्ट्रीयता है। जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को अपना सगा संबन्धी समझने लगता है। यह राष्ट्रीय बोध एक दूसरे को इतनी मजबूती से एक सूत्र में बाँधे रहता है कि आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय एकता का मर्म तथा सार है।” पार्टी के हर सदस्य में राष्ट्र के लिये गहन मानवीय बोध है-

**“अजीब कौम का रिश्ता है इन्सानियत से मेरा,**

**दर्द किसी का भी हो अहसास मुझे होता है।”**

बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मूल तत्व की जो धरोहर हमें सौंपी है उसे हमने अपने राजनीतिक जीवन की अमूल्य निधि मानते हुए उसकी समुन्नति व रक्षा हेतु कार्यकरमों की दिशा अपनाई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि “हम, भारत के लोग एक सम्पूर्ण

प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोगतांत्रत्मक गणराज्य बनाने के लिये और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विवास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बन्धुता पाने के लिये गम्भीरता पूर्वक निश्चय करते हैं।”

**6.** प्रस्तावना में निहित लक्ष्य व उद्देश्य यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता, व बन्धुता को पाना ही उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी का लक्ष्य व उद्देश्य है।

**7.** पार्टी इस लक्ष्य व उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारत के इस संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहते हुए राष्ट्र की अखंडता व एकता धर्म निरपेक्षता तथा लोकतंत्र की रक्षा से युक्त समाजवाद की स्थापना के लिये कृत संकल्प है।

**8.** पार्टी के इस लक्ष्य व उद्देश्य के कारण जनता के मामले में उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी का रुख नीचे लिखे सिद्धान्तों द्वारा निर्दिष्ट है।

**9.** राज्य समाजवाद (स्टेट सोशलिज्म) को संविधान विधि द्वारा स्थापना व संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करना।

**10.** पार्टी हर भारतीय को कानून के सामने न सिर्फ समान समझेगी बल्कि समता का अधिकारी मानेगी और तदनुसार जहाँ समता नहीं है वहीं उसे बढ़ावा देगी तथा जहाँ मानी नहीं जाती वहाँ कायम करेगी।

**11.** पार्टी बिना जाति, लिंग, सम्प्रदाय एवं धर्म के भेदभाव सभी नागरिकों हेतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक न्याय दिलायेगी तथा हर प्रकार के शोषण से उन्हें मुक्ति दिलायेगी।

**12.** पार्टी प्रत्येक भारतीय को अपने निजी ढंग से उन्नति व विकास करने का पूर्ण अधिकारी मानेगी और राज्य को उसका एक साधन मात्र समझेगी।

**13.** पार्टी सभी नागरिकों को शासन के सभी संगठनों एवं कार्यलयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलायेगी विशेष रूप से शूद्रों [अनुसूचित जाति/ जन जाति, पिछड़े वर्ग] एवं अल्पसंख्यकों को।

**14.** पार्टी प्रत्येक भारतीय के आर्थिक, धार्मिक राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता का समर्थन उसी सीमा तक करेगी जहाँ तक दूसरे भारतीयों तथा राज्य के लिये बाधक न हो।

**15.** पार्टी का शासन बतौर नीति के किसी धर्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी परन्तु धर्म निरपेक्ष होने के नाते सभी धार्मिक स्थल उसके अनुयाईयों हेतु खुले रखे जायेंगे।

**16.** पार्टी प्रत्येक भारतीय के समानता के अधिकार समर्थन इस शर्त के साथ करेगी कि पहले उन लोगों को अवसर दिया जाय जिन्हें अब तक अवसर प्राप्त न था। बाद में उन लोगों को जिन्हें पहले से प्राप्त है।

**17.** पार्टी प्रत्येक भारतीय को दासता, दरिद्रता भय और अभाव से मुक्त कराने के लिये संघर्ष करते हुए राज्य को सदैव सचेत करती रहेगी।

**18.** पार्टी स्वतंत्रता, समता, और बंधुता के प्रतिपालन पर बल देगी। तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के वर्ग और राष्ट्र के शोषण और दलन को मिटा देने में प्रयत्नशील रहेगी।

**19.** पार्टी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता सम्प्रदाईक सौहाद्रता तथा धार्मिक सहनशीलता को न केवल कायम रखेगी बल्कि इनको सुदृढ़ बनाने का हर सम्भव प्रयास करेगी।

**20.** पार्टी अन्तरराष्ट्रीय शान्ति, भ्रातृत्व एक दूसरे को समझने, आपसी सहयोग तथा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिये कार्य करेगी तथा युद्ध रहित विश्व की स्थापना हेतु विश्व के शक्तिशाली साधनों में संगठनों का उपयोग करेगी।

**21.** पार्टी शासन की संसदीय प्रणाली का समर्थन करेगी क्यों कि यह सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के कारण जनता और व्यक्ति दोनों के लिये हितकर है।

**22.** पार्टी भारत की दबी, पिंसी जनता खास कर बौद्धों और अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम व अन्य पिछड़ी जातियों संगठन व कल्याण मे लगेगी ।

**23.** पार्टी सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्य मे लगेगी ।

**24.** पार्टी उन व्यक्तियों के कार्य में सुधार लायेगी जो अस्वच्छ पे"ा में लगे हैं ।

**25.** पार्टी उत्पादनों के साधनों का न्यायोचित वितरण करेगी पूर्ण रोजगार उपलब्ध करायेगी और यदि किसी असम्पन्न नागरिक को रोजगार देने मे कमी हुई तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा । सभी नागरिकों का अनिवार्य बीमा होगा तथा समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जायेगा । वेतन मे एक और दस से अधिक का अन्तर न होगा ।

**26.** पार्टी जमीन का बन्दोबस्त करायेगी तथा अधिकतम भूमि सीमा का सिद्धान्त कर निकली हुई जमीन भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों प्रति परिवार एक हल की खेती के हिसाब से वितरित करायेगी । बाग व निजी तथा सहकारी फार्म सभी सीलिंग के अर्न्तगत माने जायेगे ।

**27.** पार्टी उन सभी लोगो को चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित बेरोजगार मानकर उन्हें रोजगार में लगायेगी जिनके परिवार के पास गुजारे लायक कोई पे"ा नही है ।

**28.** पार्टी ग्रामीण जनता को आवसीय व्यवस्था का हल इस ढंग से करेगी कि हर परिवार के पास उसके अपने मकान के लिये निश्चित सीमा की आव"यक भूमि प्राप्त हो ।

**29.** पार्टी जातिविहीन बस्तियां बसाने व उनके निवासियों के मानवीय उत्थान में लगेगी ।

**30.** पार्टी शिक्षा को अनिवार्य मान कर 12 वें दर्जे तक सभी लड़के लड़कियों को नि"ुल्क शिक्षा प्रदान करगी ।

**31.** पार्टी गांवों मे म"ीनरी उद्योगों की स्थापना करेगी ।

32. किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारखाने के करीगरों व मजदूरों व अन्य मजदूरी करने वालों के संगठन व उत्थान में लगेगी।

33. पार्टी मानवीय अधिकारों से वंचित व्यक्ति, वर्ग तथा जाति व समाज को यथास्थिति से हटा कर परिवर्तन की दिशा में मानवोचित अधिकार दिलाने में प्रयत्नशील रहेगी।

34. पार्टी शिक्षा की दोहरी नीति के स्थान पर समान शिक्षा के सिद्धान्तों को लागू करेगी।

35. पार्टी हर स्तर का तथा हर प्रकार का भ्रष्टाचार विशेष रूप से राजनैतिक जीवन का समाप्त करेगी।

36. पार्टी सभी अल्पसंख्यकों के साथ न्याय और समव्यवहार को सुनिश्चित करने के लिये संघर्ष करेगी।

37. पार्टी सभी भारतीयों के चारित्रिक एवं अध्यात्मिक उत्थान के लिये सभी कार्यवाही करेगी।

38. पार्टी कला एवं दस्तकारी सिखाने वाले स्कूलों की स्थापना जैसे शैक्षणिक कार्यों को करेगी।

39. दबे, पिछड़े, शोषितों, दलितों, पीड़ितों पर होने वाले दमन एवं अत्याचारों के अभिलेख रखेगी एवं उनको दूर करायेगी।

40. पार्टी मुद्राणालय संचालित करेगी और साहित्य का प्रकाशन करायेगी पार्टी बाबासाहेब डा० अम्बेडकर द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के साथ उपरोक्त लक्ष्य उद्देश्य एवं सिद्धान्तों की प्रतिक्रियात्मकता को प्राप्त कराने वाले हर कार्य को करेगी।

## उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी व मानव अधिकार

भारत संयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य है और दूसरे देशों में जाकर मानवधिकार की जड़ाई लड़ता है। इस दिशा में पूरी तौर पर भारत की इस लड़ाई के साथ है।

रिपब्लिकन पार्टी लम्बे अरसे से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से बराबर मांग कर रही है कि मानवीय अधिकारों के विरुद्ध होने वाले अन्याय को रोकने व मानव अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार प्रत्येक जिले में पृथक से मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करे। समय आ गया है की भारत स्वतंत्रता संग्राम के बाद मानव अधिकार का यह दूसरा स्वतंत्रता संग्राम उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी अकेले ही पूरी तैयारी और ताकत से लडेगी।

## मानव अधिकारों की सार्वभौम घोशणा

मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतरनिहित गरिमा और समान तथा अभेद्य अधिकार वि"व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार है। मानव अधिकारों की उपेक्षा और अपमान के परिणाम स्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं जिन्होंने मानव की अन्तरात्मा पर आघात किया है और ऐसे वि"व के निर्माण को जिसमें मानव वाक् स्वतंत्रता और वि"वास की स्वतंत्रता का तथा भय और आभाव से मुक्ति का उपभोग करेगें, जन सामान्य की उच्चतम आकांक्षा घोषित किया गया है।

यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलम्ब लेने के लिये विव"ा नहीं किया जाता है तो यह आव"यक है कि मानव अधिकारों का संरक्षण विधि सम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिए। यह कि राष्ट्रों के बीच मैत्री पूर्ण सम्बन्धों के विकास की वृद्धि करना आव"यक है।

संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने चार्टर में मूल मानव अधिकारों में मानव देह की गरिमा और महत्व तथा पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकारों में अपने वि"वास की पूर्ण पुष्टि की है और सामाजिक प्रगति करने तथा अधिकाधिक स्वतंत्रता के साथ उत्कृष्ट जीवन स्तर की प्राप्ति का निर्णय किया है। सदस्य राज्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्व भौम सम्मान जाग्रत करेंगे और उनका पालन करायेंगे। इन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति एक ही दृष्टि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह सफल बनाने के लिये अत्यधिक महात्वपूर्ण है।

**इसीलिये:-** मानव अधिकारों की इस महासभा सार्व भौम घोषणा को सभी लोगों और राष्ट्रों के लिये इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक सामान्य मानक के रूप में उद्घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए शिक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान जाग्रत करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रभावी उपायों के द्वारा सदस्य राज्यों के लोगों के बीच और अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच इन अधिकारों की विव्यापी और प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रयास करेगा।

### **अनुच्छेद 1-**

सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं। उन्हें बुद्धि और चेतना प्रदान की गई है उन्हें परस्पर भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए।

### **अनुच्छेद 2-**

प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता के काहकदार है इसमें मूलवर्ण, वर्ण, लिंग, भाषा धर्म और राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, संपत्ति, जन्म या अन्य प्रस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी देश या राज्य क्षेत्र की चाहे स्वाधीन हो, न्याय के अधीन हो, या प्रभुता पर किसी मर्यादा के अधीन हो, राजनैतिक अधिकारिता विषयक या अंतरराष्ट्रीय प्रस्थिति के आधार पर देश या राज्य क्षेत्र के किस व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

### **अनुच्छेद 3-**

प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है।

### **अनुच्छेद 4-**

किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नहीं रखा जायेगा की दास्ता और दास व्यापार प्रतिषिद्ध होगा।

#### **अनुच्छेद 5-**

किसी भी व्यक्ति को यातना नहीं दी जायेगी, या उसके साथ कूर अमानवीय व अपमान जनक व्यवहार नहीं किया जायेगा या उसे ऐसा दण्ड नहीं दीया जायेगा।

#### **अनुच्छेद 6-**

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है।

#### **अनुच्छेद 7-**

सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। सभी व्यक्ति इस घोषण के अतिक्रमण में विभेद के विरुद्ध और ऐसे विभेद के उद्दीन के विरुद्ध समान संरक्षण के हकदार हैं।

#### **अनुच्छेद 8-**

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

#### **अनुच्छेद 9-**

किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तार निसद्ध या निर्वसित नहीं किया जायेगा।

#### **अनुच्छेद 10-**

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों बाध्यताओं के ओर उसके विरुद्ध अपराधिक आरोप के अवधारण में पूर्णतया समान रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

#### **अनुच्छेद 11-**



ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडित अपराध का आरोप है यह अधिकार है कि उसे तब तक निरपराध माना जायेगा जब तक कि उसे लोक विचारण, में जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिये आव"यक सभी गारंटियों प्राप्त हो विधि के अनुसार दोषी साबित नहीं कर दिया जाता।

किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण जो किये जाने के समय राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध नहीं था, किसी दांडिक अपराध का दोषी निर्धारित नहीं किया जायेगा। उस शास्ति से अधिक शास्ति से अधिरोपित नहीं की जायेगी। उस समय लागू थी जब अपराध किया था।

**अनुच्छेद 12.** किसी भी व्यक्ति की एकातंता, कुटुंब, घर या पत्र व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और उसके सम्मान और ख्याति पर प्रहार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरुद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

**अनुच्छेद 13-** प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।

1. प्रत्येक व्यक्ति को, अपने दे"ा को या किसी भी दे"ा को छोड़ने और अपने दे"ा में वापस आने का अधिकार है।

**अनुच्छेद 14-**

- 1 प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य दे"ों में भी शरण माँगने और लेने का अधिकार है।
- 2 इस अधिकार का अरानैतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल कार्यों से वास्तविक रूप से उद्भूत अभियोजनों की दे"ा में नहीं लिया जा सकेगा।

**अनुच्छेद 15-**

- 1- प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।

**2-** किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रियता से और न राष्ट्रियता परिवर्तन करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

### **अनुच्छेद 16-**

- 1-** वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को, मूल वंश, राष्ट्रियता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह के विषय में, विवाहीत जीवन काल में और उनके विघटन पर समान अधिकार के हकदार हैं।
- 2-** विवाह के इच्छुक पक्षकारों की स्वतंत्र और पूर्ण सम्मति से ही विवाह किया जायेगा।
- 3-** कुटुम्ब, समाज की नैसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है और इससे समाज और राज्य द्वारा संरक्षण का अधिकार है।

### **अनुच्छेद 17-**

- 1-** प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।
- 2-** किसी को भी उसकी सम्पत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जायेगा।

### **अनुच्छेद 18-**

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार की उत्पत्ति अपने धर्म या विवासा को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या अकेले शिक्षा, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म या विवासा को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है।

### **अनुच्छेद 19-**

प्रत्येक व्यक्ति को अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार के अर्न्तगत हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम

से और सीमाओं का विचार किये बिना जानकारी माँगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता भी है।

### **अनुच्छेद 20-**

1. प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति को किसी संगम में सम्मिलित होने के लिये विवर्णन नहीं किया जायेगा।

### **अनुच्छेद 21-**

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्रता पूर्वक चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समान पहुँच का अधिकार है।
3. लोकमत सरकार के अधिकार का आधार होगा, इसकी अभिव्यक्ति आवधिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी, जो सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या समतुल्य स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया द्वारा किये जायेंगे।

### **अनुच्छेद 22-**

प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के सदस्य के रूप में, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। और वह राष्ट्रीय प्रयास और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के संसाधनों के अनुसार ऐसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है जो उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व उनमुक्त विकास के लिये अनिवार्य है।

### **अनुच्छेद 23-**

- 1- प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का, नियोजन के स्वतंत्र चयन का, कार्य की न्यायोचित और अनुकूल दशाओं का और बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है।

- 2- प्रत्येक व्यक्ति को किसी विभेद के बिना समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार है।
- 3- प्रत्येक व्यक्ति को, जो कार्य करता है, न्यायोचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है जिससे स्वयं उसका और उसके कुटुम्ब का मानव गरिमा के अनुरूप जीवन सुनिश्चित हो जाय। और यदि आवश्यक हो तो, सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसे अनुपूरित किया जाय।
- 4- प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण के लिये व्यवसाय संघ बनाने और उसमें सम्मानित होने का अधिकार है।

#### अनुच्छेद 24-

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, जिसके अन्तर्गत कार्य के घंटों की सीमा और वेतन सहित आवधिक छुट्टियां भी हैं।

#### अनुच्छेद 25-

- 1- प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन के स्तर का अधिकार है, जो स्वयं उसके और उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये प्रयाप्त है, जिसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवश्यक सामाजिक सेवायें भी हैं, और बेरोजगारी रूग्णता, अकतता, वृद्धावस्था वैधव्य या उसके नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों में जीवन यापन के अभाव की दशा में सुरक्षा का अधिकार है।
- 2- मातृत्व और बाल्यकाल विशेष देखभाल और सहायता के हकदार है। सभी बच्चे चाहे उनका जन्म विवाहित के जीवन काल में हुआ हो अन्यथा, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करेंगे।

#### अनुच्छेद 26-

- 1- प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और

वृत्तिक शिक्षा साधरणतः उफ्लबध कराई जायेगी और उच्च शिक्षा, सभी व्यक्तियों को गुणागुण के आधर पर प्राप्त होगी ।

- 2- शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर की बृद्धि होगी। यह सभी राष्ट्रों, मूलवर्गों विषयक या धार्मिक समूहों के बीच सदाचार,साहिष्णुता और मैतिरी की अनु बृद्धि के लिये श्रेष्ठ होगी और शांति बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों को अग्रसर करेगी।
- 3- मता पिता को यह चयन करने का पुर्वाधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की शिक्षा दी जायेगी।

### अनुच्छेद 27-

- 1- प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सास्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने और वैज्ञानिक प्रगाति और उसके कायदों से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।
- 2- प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिरमित वैज्ञानिक, साहित्यतिक या कलात्मक कृति के परिणाम स्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है।

### अनुच्छेद 28-

प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

### अनुच्छेद 29-

- 1- प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का उनमुक्त और पूर्ण विकास संभव है।
- 2- प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में वही मर्यादायें लगाई जायेगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सम्यक

मान्यता और सम्मान सुनिश्चित करने और प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण की न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिये विधि द्वारा की गयी है।

**3-** किसी भी दृष्टि में इन अधिकारों, स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रयोग नहीं किया जायेगा।

### अनुच्छेद 30-

इस घोषणा की किसी बात का निर्वाचन नहीं किया जायेगा कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिये कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका लक्ष्य इसमें उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना है।

उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के सभी महानभावों से अनुरोध है कि पार्टी के इस साहित्य का आम जनता में व्यापक प्रचार कर मानवाधिकार की प्राप्ति के लिये जनमत जागत करें। हमारा आन्दोलन बिना खूनी कान्ति के बुद्ध के साम्यवादी या मानववादी सिद्धान्त के आदर्श पर चलेगा और चलता ही रहेगा।

## पार्टी द्वारा समय-समय पर की गई मांगें

रिपब्लिकन पार्टी ने अपने जन्मकाल 1956 से चालू वर्ष 1989 तक अनेक सत्याग्रह प्रदर्शन व आन्दोलन किये। इन अवसरों पर जो ज्ञापन प्रस्तुत हुए उनमें प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:-

1. भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डा० अम्बेडकर का चित्र संसद भवन के सेंट्रल हाल में लगाया जाय।
2. लखनऊ में विधान भवन के निकट रायल होटल के स्थान पर बनी वाली नयी इमारत का नाम “बाबासाहेब डा० अम्बेडकर भवन” रखा जाय। उसके जिस हिस्से

मे बाबा साहेब ठहरे थे उसे उनके नाम पर ऐतिहासिक स्मारक स्थल के रूप मे निर्मित किया जाय ।

3. सभी पाठक पुस्तकों मे बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर का जीनव प्रकाशित कराया जाय ।

4. बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर के जन्म दिन 14 अप्रैल राजपत्रिका छुट्टी घोषित की जाय ।

5. बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को संवैधानिक सुविधायें पूर्ववत प्रदान की जाएँ ।

6. जो भूमि जोतकर अनाज पैदा करते हैं उन्हीं का राष्ट्र की भूमि पर अधिकार हो ।

7. भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

[महत्वपूर्ण उद्योगों के साथ बैंकों, खानों तथा चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण हो ।]

8. जब तक भूमि का राष्ट्रीयकरण नही होता बेकार और पर्ती जमीने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित की जाय ।

[क] भूमि सीमा कानून से बचने के लिये दबाई गयी जाली सहकारी समितियां व लिमिटेड कम्पनियां समाप्त कर दी जाएँ ।

[ख] असिंचित भूमि के नाम पर कब्जे मे लाई गयी भूमि जोकि सिंचित हो चुकी है कब्जेदारी से छीन कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित की जाय ।

9. भूमि की हदबन्दी इस प्रकार की जाय कि उसकी सीमा प्रति किसान ढाई एकड़ से कम व दस एकड़ से अधिक न हो ।

10. ग्रामीणों को सस्ते दामों में बिजली दी जाय ।

11. शहरी आबादी पर पड़ने वाली भार को कम करने के लिये बड़े उद्योगों को ग्रामों मे लगाया जाय ।

12. दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त की जाय ।

13. उत्तर प्रदेश व बिहार में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाय।
14. बढ़ती हुई मंहगाई के अनुपात से अनुसूचित/जन जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति तिगुनी की जाय।
15. लोक सेवा अयोग में उम्मीदवारों के चयन में घपले बाजी को रोकने के लिये कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि लिये जायें।
16. अल्पसंख्यों का आरक्षण उनकी आबदी के अनुपात से किया जाय।
17. पिछड़े वर्ग की सामाजिक व शैक्षिक स्थिति के अनुसार संविधान प्रदत्त सुविधाएँ देने के लिये मंडल आयोग की संस्तुतियां लागू की जाय।
18. सभी धार्मिक स्थल 15 अगस्त सन् 1947 की स्थिति में जो जिसके हों उसी के माने जाएं।
19. प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना हो।
20. भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उनके कारणों का अंत किया जाय।
21. बढ़ती हुई मंहगाई, पूँजीवाद को बढ़ावा देने व उसके बल पर सत्ता को बनाये रखने का काम है अतः इसे समाप्त किया जाय।
22. भारत निर्वाचन आयोग खर्चीले चुनाव पर प्रतिबन्ध लगाये तथा चुनाव प्रचार का खर्च पार्टी व मित्रों तथा सहयोगियों का न मानकर सीधे प्रत्याषी का माना जाय।

1- हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिये आवश्यक है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नियम बनाया जाय।

वोट की धांधली व बूथों पर कब्जेदारी को रोकने के लिये उपाय हो तथा ईमान दारी से चुनाव की प्रक्रिया के लिये प्रत्येक मतदाता के पास उसके चित्र के साथ परिचय पत्र अनिवार्य कर दिया जाय।



23. कम वेतन पाने वाले सभी मजदूरों के हित में मिनमम वेजेज ऐक्ट को सकिय रूप प्रदान किया जाय।
24. दलित वर्गों का उत्पीड़न रोका जाय।
25. अलाभकर विकास योजनाएं समाप्त कि जायं।
26. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को "ीध्राति शीघ्र पूरा किया जाय।
27. मालिन बस्तियों में रहने का उत्रति मय सुधार हो ।
28. खाद्य सामग्री वितरण की सही व्यवस्था हो तथा सस्ते गल्ले की दुकान दूर दराज जगहों व देहात के क्षेत्रों में भी खोली जाय।
29. राजस्थान के उच्चन्यालय के परिसर में लगाई गई मनु की प्रतिमा हटाई जाय क्योकि मनु के विधान का भारतीय संविधान से कोई मेल नहीं है।
30. भारतीय संविधान के प्रमुख िल्पी बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के चित्र भारत के प्रत्येक न्यायालय और सरकारी कार्यलयों में लगायें जायं। हमने यहाँ उन मांगों तथा आन्दोलनों का जिक्र नहीं किया है। जो कि महात्मा जोतिबा फूले तथा स्वामी अछूतानन्द जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों के नेतृत्व में सामाजिक कान्ति के रूप में उभरे थे। उन घटनाओं का भी जिक्र नहीं है जो दे"ा की स्वराज्य की लडाई के साथ ही जनता के स्वराज्य के लिये लड़े गये थे। उनका जिक्र नहीं है जो शेडयूल्ड कास्ट फेडरे"ान से पूर्व डीप्रस्टक्लास बहिष्कृतक्लास आदि विभिन्न नामों से दे"ा के कोने-कोने से अपनी मांगों के आन्दोलन में कुंबान थे।

बाबा साहेब ने सच ही कहा था कि उन्हांने दलित समाज को ििक्षित बनाने के लिये जितना संघर्ष किया उतना यदि भूमि-हीनों को भूमि दिलाने के लिये करते तो ज्यादा कल्याण होता। वे कितने बडे दूर द"र्षि थे जिन्हें दलित समाज के इन बाबुओं स पहले ही समाज के हित की आ"ा क्षीण हो चुको थी। उनका सोचना सही ही है कि आज वे बाबासाहेब की

रिपब्लिकन पार्टी का जाने अनजाने विरोध करते हुए उन्हीं का त्याग व तपस्या तथा परिश्रम की बदौलत प्राप्त धन व समय को खर्च कर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

## साथी रिपब्लिकन महानुभाव

रिपब्लिकन पार्टी के संबन्ध में इस पुस्तक को बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखने की सबसे पहली मेरी कोशिश यह रही कि दे"ा के समस्त रिपब्लिकन पार्टी के नाम धारी नेता व कार्यकर्ता सच्चे व साफ मन से एकता में लीन हो बाबा साहेब की रिपब्लिकन पार्टी को राष्ट्र की पार्टी बनाने का बीड़ा उठाकर पुनः जाग्रत हो जो रिपब्लिकन पार्टी को किन्ही कारणों से छोड़ कर कहीं चले गये हों पुनः वापस आयें।

बाबा साहेब की रिपब्लिकन पार्टी के संविधान की ही नकल नहीं बल्कि झण्डें की भी नकल व चुनाव चिन्ह हाथी को लेकर उत्तर भारत खास कर उत्तर प्रदेश"ा में जनता को जितना गुमराह कर रिपब्लिकन पार्टी को समाप्त करने का 'डण्डयंत्र' किया गया वह अब साक्षात् हो चुका है। साफ है कि रिपब्लिकन पार्टी के रहने से बाबा साहेब का नाम व उनका मि"ान उजागर होगा। बाबा साहेब का नाम लेकर उनके मि"ान की दुहाई देकर अपनी पार्टी चलाने वाले के पीछे चलने वाली भ्रामक भीड़ जिसे अपना रास्ता ही नहीं मालूम ज्ञात होने पर रिपब्लिकन पथ को अपनाएगी। मेरे विचार से यह हमारी ही कमी है की जिस कारण बाबा साहेब की जुझारू फौज का हमारा काम न होने से रूख बदल गया। हम सही चलेंगे तो दूसरे कारवां में लगे लोग हमें चलते देख स्वतः इस कहावत को चरितार्थ कर देंगे की "नीम का छिलका नीम में ही लगता है" उत्तर प्रदेश"ा के समस्त विवेक "ील लोगों ने निर्णय किया की वे रिपब्लिकन पार्टी को एक इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश"ा में गठित कर आगे बढ़ायेगें। हमारे इस गठन की मान्यता भारत निर्वाचन आयोग से तब मिल पाई जब की नामकंन पत्र की वापसी का समय था। इसके बाद आयोग के हिन्दी गजट में फिर गडबड़ी हुई और उसे सही करने की सुचना की 1 नवम्बर 1989 को तब मिली जब कि 24 नवम्बर से वोटों की

गिनती प्रारम्भ थी। यह घटना हमारे दल के चरित्र का एक नमूना है। पार्टी की रजिस्ट्री को लेकर बाधा अव्यय उत्पन्न हुई जिसका असर मतों पर पड़ा। किन्तु विचारों में युद्ध स्तर का उत्साह बराबर बरकरार है।

10 दिसम्बर सन् 1948 को संयुक्त राष्ट्र सघ की ओर से मानव अधिकार घोषण पत्र जारी हुआ था। वस्तविकता यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का संघर्ष ही मानव अधिकार का क्षेत्र है इसलिये भारत में इस दूसरे स्वतंत्रता संग्राम “मानव अधिकार” के निश्चित हम इस घोषण पत्र के साथ दिनांक 10 दिसम्बर सन् 1989 ई0 को देना की रिपब्लिकन जनता के नाम रिपब्लिकन पार्टी के नाम उत्थान के निर्मित यह पुस्तक भेंट कर रहे हैं।

इसी बीच विधान सभा क्षेत्र सिकंद्राबाद जिला बुलन्द शहर के रिपब्लिकन प्रत्याग्नी श्री संकटू सिंह को गोली मार दी गई। वे शहीद हो गये उन्हें प्रलोभन दिया गया था कि वे बीस हजार रूपये लेकर चुनाव मैदान से हट जाएँ। शहीद संकटू सिंह जी ने मरना कबूल किया पर सिद्धान्त नहीं छोड़ा। हमने प्रतिज्ञा की है कि उनकी शहादत में हम पार्टी को अमर बनाएंगे।

लेखक

निर्वाण प्राप्त- डा0 गया प्रसाद

प्रज्ञान्त

552/2 राजेन्द्र नगर दूसरा मार्ग

लखनऊ 226004 उत्तर प्रदेश